

न्यूज़ डुडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा है कि वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया के लिए 'मध्यस्थता (Arbitration)' सबसे अच्छा विवाद समाधान तंत्र है

हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में, CJI ने वैश्वीकृत दुनिया के लिए एक स्वीकार्य और निष्पक्ष विवाद समाधान प्रणाली विकसित करने के महत्व की ओर इशारा किया। साथ ही, उन्होंने विवाद समाधान तंत्र के संबंध में मध्यस्थता को एक सर्वोत्तम प्रणाली करार दिया।

○ **मध्यस्थता (Arbitration):** यह एक प्रकार का वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution: ADR) तंत्र है। इसके तहत विवाद को एक मध्यस्थ अधिकरण (Arbitral Tribunal) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा विवाद पर दिया गया निर्णय, अधिकतर मामलों में संबंधित पक्षकारों (पार्टीज) के लिए बाध्यकारी होता है।

➤ ADR: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जहाँ संबंधित पक्षकारों के बीच विवादों को अदालतों के हस्तक्षेप के बिना और बिना किसी कानूनी पचड़े के सुलझाया जाता है।

○ मध्यस्थता को आम तौर पर मुकदमेबाजी (Litigation) की तुलना में अधिक कुशल प्रक्रिया माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यस्थता एक तीव्र व कम खर्चीली प्रणाली है। साथ ही, यह एक अत्यधिक लचीली प्रक्रिया और कार्यप्रणाली भी प्रदान करती है।

➤ निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

○ मध्यस्थता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ आवश्यक व अनिवार्य शर्तें:

➤ इसके लिए शुरू से लेकर किसी फैसले या पंचाट (award) को चुनौती देने तक न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम से कम करने की आवश्यकता होती है।

➤ मध्यस्थ प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

➤ संबंधित पक्षकारों की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए।

➤ विवाद समाधान से संबंधित लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अधिक-से-अधिक मध्यस्थता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।



14वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ

○ हाल ही में सम्पन्न 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान "भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी (India-Japan Special Strategic and Global Partnership)" को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

➤ भारत और जापान, दोनों क्वाड तथा आसियान ग्रुपिंग में शामिल हैं। साथ ही, दोनों देश हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के संबंध में भी एक साझा दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

➤ भारत पिछले कुछ सालों से जापानी आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है।

○ 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन पर एक नज़र:

➤ इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (Clean Energy Partnership: CEP) की शुरुआत की। इसे वर्ष 2007 में स्थापित "भारत-जापान ऊर्जा वार्ता" के समग्र दायरे के तहत आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में सहयोग करना है:

- सतत आर्थिक विकास हासिल करने के संबंध में,
- जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के संबंध में, और
- ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में।

➤ इस दौरान संयुक्त क्रेडिट तंत्र (Joint Crediting Mechanism) की स्थापना हेतु आगे भी चर्चा जारी रखने पर प्रतिबद्धता दोहराई गई। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में निजी पूंजी प्रवाह से संबंधित पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

➤ दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन (Memorandum of Cooperation: MoC) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

➤ जापान LeadIT नामक जलवायु पहल में शामिल होगा। यह भारत और स्वीडन के बीच एक प्रकार का जलवायु पहल है। इसे भारी उद्योग में रूपांतरण को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है।

■ यहाँ LeadIT का आशय उद्योग में रूपांतरण के लिए नेतृत्वकारी समूह (Leadership Group for Industry Transition: LeadIT) से है। यह कम कार्बन की दिशा में आगे बढ़ने हेतु एक स्वेच्छिक पहल है। इसके तहत विशेष रूप से लौह और इस्पात, एल्यूमीनियम, आदि जैसे हार्ड-टू-एबेट सेक्टर (hard-to-abate sectors) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

● **हार्ड-टू-एबेट सेक्टर:** यह ऐसे क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जहाँ अन्य क्षेत्रों की तुलना में रूपांतरण (transformation) कठिन होता है। इस क्षेत्र में तकनीक की कमी या अधिक लागत के चलते रूपांतरण मुश्किल हो जाता है।

➤ साथ ही, भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2023-2024 हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अस्थायी सीट के लिए जापान की उम्मीदवारी के संबंध में भारत के समर्थन को दोहराया गया।

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6: यह कुछ पक्षकारों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDCs) के कार्यान्वयन में स्वेच्छिक सहयोग को जारी रखने को मान्यता प्रदान करता है। इसके तहत पक्षकार अपने शमन (mitigation) और अनुकूलन (adaptation) कार्यों में उच्च महत्वाकांक्षा के साथ-साथ सतत विकास एवं पर्यावरणीय अखंडता को बढ़ावा देते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR), 2022 जारी की

- इस वर्ष रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र में जी.डी.पी., सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए खुशी (यानी हैप्पीनेस) के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है।
 - इस रिपोर्ट का लक्ष्य कल्याण (well-being) के प्रमुख निर्धारकों (determinants) की पहचान करना है।
- वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत, 136वें स्थान पर है। फिनलैंड, लगातार 5वें वर्ष सूची में सबसे ऊपर है। इसे दुनिया के सबसे खुशहाल देश के तौर पर चुना गया है।
 - WHR, 2022 की रैंकिंग में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक के गैलप वर्ल्ड पोल सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग किया गया है।
 - इस सूचकांक में नीचे के पांच स्थानों पर निम्नलिखित संघर्षग्रस्त देश शामिल हैं— अफगानिस्तान, लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना।
 - भूटान, इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था।
- इस साल के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है, जहाँ पिछले 10 वर्षों में, जीवन मूल्यांकन (life evaluations) के मामले में 0 से 10 के पैमाने पर एक अंक से अधिक की गिरावट देखी गयी है।
- इस रिपोर्ट की आलोचना: इस रिपोर्ट को तैयार करते समय आबादी के केवल एक छोटे से हिस्से को शामिल किया जाता है। ऐसे में साधारण नतीजों के आधार पर एक देश की खुशहाली का मापन करने के चलते इसकी आलोचना की जाती है।

सतत विकास समाधान नेटवर्क (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) के बारे में

- इसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता जुटाता है। साथ ही, यह सतत विकास के लिए व्यावहारिक समाधान को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है।

गुजरात में आदिवासी समुदाय तापी, पार और नर्मदा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना का विरोध कर रहे हैं

- इन नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के तहत की गई है। इसके तहत पश्चिमी घाट के जल अधिकता वाले क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के जल की कमी वाले क्षेत्रों में नदी जल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

- राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan: NPP): इसे राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (National River Linking Project: NRLP) के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत जल अधिकता वाली जलमग्न नदी घाटियों से सूखे या जल की कमी वाली नदी घाटियों में जल स्थानांतरण की परिकल्पना की गई है।

- इसमें तीन नदियों, यथा— पार (महाराष्ट्र के नासिक से उद्गम), तापी (सतपुड़ा से निकलने वाली) और नर्मदा (मध्य प्रदेश में उद्गम) को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है।

- इसके तहत सात बांधों (झेरी, मोहनकवचली, पाइखेड़, चासमांडवा, चिक्कर, डाबदार और केलवान) का निर्माण किया जाना है। इनमें से एक महाराष्ट्र में और अन्य गुजरात में स्थित होंगे।

○ महत्व:

- यह सरदार सरोवर बांध के जल की बचत करने मदद करेगा, जिसका उपयोग वर्तमान में सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई के लिए किया जाता है।

- इस परियोजना के तहत चार बांध स्थलों (डैम साइट्स) पर बिजलीघरों का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार, इससे जल विद्युत उत्पादन में सहायता मिलेगी।

- इन बांधों के कारण निर्मित होने वाले जलाशयों से नदी के प्रवाह की दिशा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बाढ़ से भी राहत मिलेगी।

- हालांकि, आदिवासियों द्वारा मुख्य रूप से भूमि के जलमग्न होने, विस्थापन और आजीविका के नुकसान के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है।



केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)' की सहायता से छोटे खुदरा विक्रेता, आधुनिक डिलीवरी सिस्टम अपना सकेंगे

- ONDC, विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला प्रयास है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना तथा खरीदारों एवं विक्रेताओं, दोनों के लिए उद्योग को अधिक समावेशी बनाना है।

- यदि सरकार इसे एक सरल ओपन-सोर्स बनाने में कामयाब हो जाती है, तो यह भारत की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति हो सकती है।

- यह ओपन-सोर्स पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देता है। इसके तहत ओपन स्पेसिफिकेशन्स (मुक्त विनिर्देशों) और नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। साथ ही, यह किसी विशेष प्लेटफॉर्म से भी स्वतंत्र होता है।

- ओपन सोर्स प्रक्रिया/सॉफ्टवेयर: इसके तहत किसी प्रक्रिया के लिए उपयोग की गई तकनीक या कोड को सभी के द्वारा इस्तेमाल करने, पुनर्वितरित करने और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने का कार्य भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) को सौंपा गया है।

- ONDC को वर्ष 2021 में एक निजी क्षेत्र की गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।

- ONDC को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रोजेक्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है।

○ ONDC का महत्व:

- यह एकल नेटवर्क स्थापित करने के लिए साइलो व्यवस्था का समापन कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। यह सभी व्यवसायों में रूपांतरण, नवाचार और विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इन व्यवसायों में खुदरा वस्तुओं व खाद्य पदार्थों के कारोबार से लेकर मोबिलिटी व्यवसाय तक शामिल हैं।

- इसके तहत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक-समान प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा अपना परिचालन करना पड़ेगा। इस प्रकार यह बेहतर पहुंच और इंटर पोर्टेबिलिटी प्रदान कर छोटे ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ नए अभिकर्ताओं को भी बढ़ावा देगा।

अन्य सुर्खियाँ



बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021 (Bihar Land Mutation Amendment Bill, 2021)

- बिहार अपने यहाँ के गाँवों के लिए एक परिवर्तनशील नक्शे (**dynamic map**) की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। यह नक्शा भू-स्वामित्व के हस्तांतरित होने के साथ ही उसके अनुरूप अपडेट हो जायेगा।
- इस प्रकार, प्रत्येक बार स्वामित्व बदलने पर, निम्नलिखित तीन परिवर्तन होंगे— पहला, पाठ (**text**) में बदलाव आएगा; दूसरा, संपत्ति भूखंड (**land parcel**) में परिवर्तन होगा; तथा तीसरा, सर्वेक्षण मानचित्र (**survey map**) में संशोधन होगा।
 - इससे पहले केवल पाठ्य रिकॉर्ड्स (**textual records**) का ही दाखिल खारिज होता था।
- यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह कानूनी विवादों में कमी करेगा। साथ ही, काफी समय से लंबित रहे भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में भी मदद करेगा।



सं परिवर्तनीय नोट (Convertible note)

- सरकार ने स्टार्ट-अप्स के लिए **कनवर्टिबल नोट्स** को **इक्विटी शेयरों** में बदलने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। इसे पहले के पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया गया है।
- **कनवर्टिबल नोट** एक प्रकार का लिखत (**instrument**) होता है। इसे एक स्टार्ट-अप जारी करता है। यह शुरू में ऋण के तौर पर पूँजी जुटाने का एक साधन है। इस शुरूआती पूँजी को बाद में या तो चुका दिया जाता है या पूँजी के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाता है।
- प्रायः एंजेल अथवा सीड निवेशक **कनवर्टिबल नोट** के जरिये निवेश करते हैं। ये निवेशक ऐसे नए स्टार्ट-अप्स में निवेश करते हैं, जो बाजार में अभी पूरी तरह से अपना पाँव पसारने में समर्थ नहीं हैं।



गोल्डन लंगूर

- हाल ही में, वैज्ञानिकों के एक दल ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार, गोल्डन लंगूर के पर्यावास (**हैबिटेट**) में गंभीर रूप से गिरावट आ रही है।
- गोल्डन लंगूर (या सुनहरा लंगूर) को उसके सोने जैसे रंग वाले फर (**fur**) के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह भारत और भूटान में पाया जाता है।
 - गोल्डन लंगूर का पर्यावास उत्तर में भूटान के फूटहिल्स, पूर्व में मानस नदी, पश्चिम में संकोश नदी और दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित है।
 - यह संकटग्रस्त वन्यजीवों एवं वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (**CITES**) के एपेंडिक्स I में सूचीबद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (**IUCN**) की संकटापन्न (थ्रेटेंड) प्रजातियों की लाल सूची में 'एंडेंजर्ड' के रूप में शामिल है।
 - यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में भी सूचीबद्ध है। उल्लेखनीय है कि भूटान ने भी इसे अपने फ़ॉरेस्ट एंड नेचर कंजर्वेशन एक्ट, 1955 के अधीन संरक्षण प्रदान किया है।
 - खतरे — विद्युत करंट से मौत, वनों की कटाई, पर्यावास की हानि, आदि।



केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park (KNP))

- केवलादेव से हिरणों के स्थानांतरण के लिए अफ्रीका की **बोमा तकनीक (Boma technique)** को अपनाया गया है।
 - इस तकनीक में जानवरों को भोजन का लोभ देकर एक सुरक्षित बाड़े में ले जाया जाता है।
 - पहले यह तकनीक अधिकतर प्रशिक्षण या देखभाल हेतु जंगली हाथियों को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती थी।
- केवलादेव को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है।
 - यूनेस्को ने इसे वर्ष 1985 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया था।
 - इसे वर्ष 1981 के रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है।
 - यह अति दुर्लभ साइबेरियाई सारस के प्रजनन स्थल के रूप में भी विख्यात है।



कामिकेज़ ड्रॉन्स (Kamikaze drones)

- ये छोटे आकार के मानव रहित विमान हैं। ये विस्फोटक पदार्थों से लैस होते हैं। ये किसी टैंक अथवा सैन्य टुकड़ी के ऊपर उड़ान भर सकते हैं। इनसे टकराने के बाद इनमें विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद ये काफी क्षति पहुँचाते हैं।
 - इन्हें **स्विचब्लेड ड्रॉन्स** भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लॉन्च करने पर इनके ब्लेड जैसे विंग्स निकलते हैं।
- विशेषताएं: इन्हें राडार की सहायता पता लगा पाना कठिन होता है। ये बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये फ़ेशियल रिकग्निशन तकनीक पर आधारित होते हैं। ये विस्फोट के दायरे को सीमित कर सकते हैं। साथ ही, ये लागत प्रभावी भी होते हैं।
- हाल ही में, इनकी रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन को आपूर्ति की जा रही है। यह आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जा रही है।
 - रूस, चीन, इजरायल, ईरान और तुर्की सहित कई अन्य देशों के पास भी इसका कोई न कोई संस्करण मौजूद है।



नरसिंगनपेट्टई नादस्वरम

- नरसिंगनपेट्टई नादस्वरम तंजावुर के एक गाँव नरसिंगनपेट्टई से संबंधित एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। हाल ही में, इसे **भौगोलिक संकेतक (GI)** का दर्जा प्रदान किया गया।
 - यह एक जटिल संगीत वाद्य यंत्र है। यह माना जाता है कि 13वीं सदी में इसका उद्गम हुआ था।
- इस वाद्य यंत्र को "आचा मरम" नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। यह वृक्ष अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है।
 - आचा लकड़ी प्राकृतिक रूप से वाटर रेज़िस्टेंट होती है। इसे विशेष रूप से वाद्य यंत्र बनाने के लिए कावेरी नदी बेसिन से प्राप्त किया जाता है।
- कारीगर नादस्वरम बनाने के लिए ड्रिल मशीनों का उपयोग करते हैं। इस वाद्य यंत्र का विवाह समारोह व मंदिर उत्सव जैसे कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है।



सुर्खियों में रहे स्थल

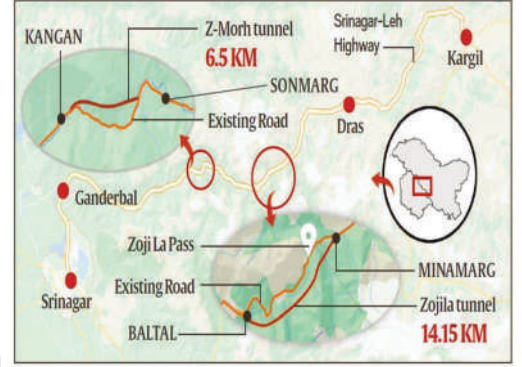
काला सागर (Black Sea)

- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण काला सागर से होकर गुजरने वाला पोत परिवहन मार्ग बंद हो गया है।
- काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है। यह दक्षिण-पूर्वी यूरोप व अनातोलिया प्रायद्वीप (तुर्की) के मध्य स्थित है।
- यह भूमध्य सागर और एजियन सागर तथा विभिन्न जलडमरूमध्यों के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है।
- बोस्फोरस जलडमरूमध्य इसे मरमारा सागर से जोड़ता है। डारडेनेल्स जलडमरूमध्य इसे भूमध्य सागर के एजियन सागर क्षेत्र से जोड़ता है।
- उत्तर में, यह केच जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है।



जोजिला दर्रा (Zoji La Pass)

- सीमा सड़क संगठन (BRO) ने श्रीनगर-कारगिल-लेह सड़क पर दुर्गम जोजिला दर्रे को रिकॉर्ड 73 दिनों में खोल दिया है।
- यह 11,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक सामरिक दर्रा है। यह कश्मीर घाटी व लद्दाख के बीच महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह सशस्त्र बलों की अभियान संबंधी तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- सरकार, 14.15 कि.मी. लम्बी एक जोजिला सुरंग का निर्माण कर रही है। यह देश की सबसे लम्बी सड़क मार्ग सुरंग होगी। साथ ही, यह एशिया महाद्वीप की दो दिशाओं वाली सबसे लम्बी सुरंग होगी।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



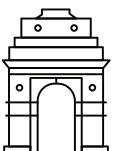
/Vision_IAS



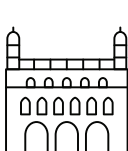
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



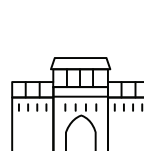
लखनऊ



जयपुर



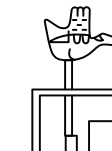
हैदराबाद



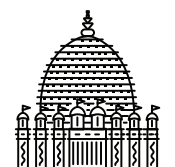
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी